भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2399
08 अगस्त, 2025 को जवाब दिया

वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना का कार्यान्वयन और प्रारंभिक परिणाम

2399. श्रीमती संगीता यादव:
डा. कविता पाटीदार:
श्री मिथलेश कुमार:
डा. सुमेर सिंह सोलंकी:
श्री नारायण कोरागप्पा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को वस्त्र मूल्य श्रृंखला में बड़े निर्माताओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) दोनों की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए किस प्रकार तैयार किया गया है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत घरेलू उत्पादन और निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए रेखांकित किए गए निवेश प्रतिबद्धताएँ और कारोबार अनुमान क्या हैं; और
(ग) भारत की वस्त्र प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में इस योजना की प्रभावशीलता को दर्शाने वाली शुरुआती उपलब्धियाँ या सफलता की कहानियाँ क्या हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): भारत सरकार देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रही है ताकि वस्त्र क्षेत्र को आकार और पैमाना हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के दो भाग हैं; भाग 1 में प्रति कंपनी न्यूनतम 300 करोड़ रुपये का निवेश और 600 करोड़ रुपये के न्यूनतम कारोबार की परिकल्पना की गई है; और भाग-2 में प्रति कंपनी न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का निवेश और 200 करोड़ रुपये के न्यूनतम कारोबार की परिकल्पना की गई है, ताकि बड़े पैमाने के विनिर्माताओं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों (एमएसएमई) दोनों की भागीदारी को आकर्षित किया जा सके। प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र बनने के लिए, कंपनी को उपरोक्त सीमा निवेश और कारोबार हासिल करना होगा। इस योजना के तहत, कुल 74 कंपनियों को चुना गया है, जिनमें से 24 कंपनियां एमएसएमई श्रेणी में हैं।

(ख) और (ग): इस योजना के अंतर्गत अनुमानित निवेश और कारोबार क्रमशः 28,711 करोड़ रुपये और 2,16,760 करोड़ रुपये है, जिसमें निर्यात भी शामिल है। दिनांक 31/03/2025 तक, पीएलआई प्रतिभागी कंपनियों द्वारा किया गया कुल निवेश 7,343 करोड़ रुपये है और कुल कारोबार 4,648 करोड़ रुपये है, जिसमें 538 करोड़ रुपये का निर्यात भी शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत 54.50 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन वितरित किया जा चुका है।

****